भाजपा का काला चिट्ठा

- 9 साल मोदी सरकार की वादाखिलाफी
- 15 साल रमन राज में छत्तीसगढ़ का शोषण, भ्रष्टाचार, लूट वादाखिलाफी
- भाजपा का चरित्र आदिवासी अनु. जनजाति, अनु. जाति, अ.पि.व गरीब विरोधी

नरेन्द्र मोदी सरकार का काला चिट्ठा

वादा किया था सुशासन लाने का, महंगाई कम करने का, 140 करोड़ लोगों के देश में मात्र चंद पूंजीपतियों के लिये केंद्र सरकार चला रही है।

मोदी जी जवाब दें

1. अच्छे दिन कब आयेंगे ?
2. किसके एकाउंट में 15 लाख जमा किए ?
3. महंगाई कब कम होगी ?
4. पेट्रोल–डीजल के दाम कब कम होंगे ?
5. 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया क्या ?
6. चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे ?
7. नोटबंदी से जनता को और सरकार को क्या मिला ?
8. 370 हटने से कश्मीर में कितनो ने प्लॉट खरीदा और कितनी कंपनी ने प्लांट खड़े किए ?
9. किसानों की आय दुगनी हुई क्या ?
10. बेटियां सुरक्षित क्यो नही ?
11. शिक्षा संस्थानों की हालत खस्ता क्यो ?
12. जीएसटी से व्यापारियों ने और सरकार ने क्या पाया, क्या खोया ?
13. 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, कितने स्मार्ट सिटी बने ?
14. सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव में से कितने गांव का विकास हुआ और कितने गांव अभी भी गोदी में बैठे है ?
15. स्वतंत्र आवाज़ उठाने वाले मीडिया को क्यों दबाया जा रहा है ?
16. सरकारी संपत्ति को बेच–बेच कर कब तक देश चलेगा ?
17. आपकी सरकार ने देश में कितने अस्पताल सरकारी नए खोले ?
18. आपकी सरकार ने कितने नए डेम बनाए ?
19. पुलवामा में सेना के जवानों की हत्या का जिम्मेदार कौन ?
20. जनधन के तहत खोले गए कितने एकाउंट अभी भी एक्टिव है ?
21. बिजनेश समिट में हुए कितने एमओयू कार्यरत हुए और कितने कैंसिल हुए ?
22. कितनी विदेशी कंपनियों ने भारत में कितना इन्वेस्ट किया और उसमे कितने भारतीय स्थानीय लोगो को रोजगार मिला ?
23. आपके मंत्री मंडल के कितने मंत्रियों के बच्चे भारत की सरकारी स्कूलों में पढ़ते है ?
24. स्वच्छ भारत के तहत अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है, कितने शहर स्वच्छ हुए?
25. भुखमरी के दिन ब दिन भारत निचले स्तर पर क्यों आ रहा है ?
26. बोलने की आजादी के मामले में भारत क्यों पिछड़ रहा है?
27. पिछले 9 साल में गोदी मीडिया की तादात क्यों बढ़ी ? इसका जिम्मेदार कौन ?
28. 9 साल में ईडी और आईटी की रैड कितने भाजपाई नेताओ के ऊपर पड़ी ?
29. 2014 से पहले आपके पास भ्रष्टाचारियों की फाइल होती थी, उसमे से कितने कांग्रेसियो पर कार्यवाही करते हुए जेल में भेजा ?
30. क्या आपकी सरकार में भ्रष्टाचार सम्पूर्ण नाबूद हो चुका है ?
31. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, पर आज बेटियां नेताओ की वजह से प्रताड़ित होकर दिल्ली में धरना दे रही है वो भी भाजपाई सांसद. क्या आप उस सांसद को हटा नही सकते ?
32. नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा ऐसा आपने कहा था, क्या वो हुआ ? क्या कश्मीर में भारत के जवान शहीद नही हो रहे ?
33. 9 साल में आपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए ? अगर नही तो क्यो ?
34. हेट स्पीच मामले में कितने भाजपाई नेताओं पर कार्यवाही की ?
35. आपकी सरकार में किसानों की आत्महत्या बंद हुई ?
36. मां गंगा ने आपको बुलाया था, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए पर क्या मां गंगा की सफाई पूर्ण रूप से हुई ?
37. आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने उद्योग खड़े हुए और उसमे कितने भारतीय बेरोजगारों को रोजगार मिला ?
38. 2022 में हर बेघर को अपना घर देने का वादा था, वादा कितना पूरा हुआ ?
39. आपकी सरकार ने कितने एयरपोर्ट बनाए अगर बनाए तो एयर इंडिया को बेचना क्यो पड़ा ?
40. भारत के डिफॉल्टर जो विदेश भाग गए उसमे आपकी सरकार में कितने भागे और कब वापस लाएंगे ?
41. नोटबंदी में कितने भाजपाई नेता नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े थे ? कितनो के पास आय से अधिक कलाधन मिला ?
42. विदेश में जमा काला धन कितने भारतीयों का है ? किसका है? वापस कब लायेंगे ?
43. संसद चलाने का खर्च जनता के टेक्स के पैसे से होता है, आपकी सरकार में संसद कितने समय तक चली ? और कितने समय हंगामे के कारण बंद करना पड़ा?
44. कितने उत्पादन का निर्यात बढ़ा?
45. आपकी हर एक विदेश यात्रा में कितना खर्च हुआ ?

46. पीएम पद पर रहते आपने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार भी जनता के टेक्स के पैसे से किया उनका हिसाब कौन देगा ? क्योंकि चुनाव में सरकारी सम्पतियो का उपयोग भी तो हुआ था...
47. घोषणा पत्र में किए गए कितने बड़े वादे है जो आपकी सरकार ने पूर्ण किए हो ?
48. उज्जवला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया ? उसमे से कितनो ने अपने पैसे से रिफिल करवाया ?
49. गुजरात में डबल इंजिन की सरकार होने के बावजूद शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों, बिल्डिगो में कमी क्यो ?
50. पकौड़ा, पान, पंचर उद्योग के तहत कितने यूवाओ को रोजगार मिला ?
51. 5 ट्रिलियन इकोनोमी की बाते की थी, आज अर्थव्यवस्था का हाल क्या है ?
52. 2000 की नोट आपकी सरकार ने ही लॉन्च की थी, ऐसा क्या हुआ की कम समय पर ही बंद करने का निर्णय लेना पड़ा ?
53. डॉलर के मुकाबले रूपये का हाल क्या है ?
54. कितने कश्मीरी पंडितो को विस्थापित किया गया ?
55. मणिपुर में भी डबल इंजिन की सरकार है फिर दंगे क्यो भड़के ?
56. समान नागरिक संहिता बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में हमेशा रहा है. इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने क्या किया?
57. पत्रकार जनता के सभी सवाल पूछने का बेताब हैं, मोदी जी पत्रकारों के सवालों का जवाब कब देंगे ?
58. देश का भविष्य अगर नौजवान हैं तो मोदी इन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं?
59. सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता भारतीय मुस्लिमों के ख़लिफ़ नफ़रत उगलते हैं. आप ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते ?
60. देश में प्राइमरी और हायर शिक्षा बहुत महंगी है. सरकार ने चार साल में इसके लिए क्या किया ?
61. मोदी जी आप अभी तक अपने थिंकटैंक पर चल रहे हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ?
62. आप अपने भाषणों में सुनियोजित योजना के तहत झूठ बोलते हैं या जानकारी के अभाव में ?
63. मोदी जी क्या आपको नहीं लगता कि देश समाजिक तौर पर बिखर चुका है. धर्म के नाम पर भेदभाव अपने चरम पर है ?
64. 2014 से 2023 तक किसानों की मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा ?
65. मोदी जी 70 साल को कोसना कब बंद करेंगे ?
66. 9 साल में ग़रीबों और अमीरों के बीच फ़ासले को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया ?
67. मॉब लिंचिंग कब बंद होगी मोदी जी ?
68. सरकारी नौकरियों में कमी क्यों आती जा रही है ?
69. क्या कांग्रेस मुक्त ही विकास है? बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से अगर कोई अफवाह फैलाई जाती है, तो इसके लिए आपकी जवाबदेही है ?
70. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 80 फीसदी गौरक्षक आपराधिक तत्व हैं. फिर उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती ?
71. सर, आप बुलेट ट्रेन पर रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि बहुत सारे विकास प्रोजेक्टस अब भी अधूरे हैं ?
72. क्या भारत को हिंदुराष्ट्र बनाना भी एक जुमला ही है ? क्योंकि आपकी पार्टी भी अब मुस्लिमो के वोट के लिए सहयोग मांगने लगी है ?
73. गौरक्षकों के हाथों बेकसूर लोगों के मारे जाने के बाद सरकार इस तरह की घटनाओं की खुलकर निंदा क्यों नहीं करती ?
74. मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में हमने इतनी बातें सुनीं, लेकिन उनका कोई असर क्यों दिखाई नहीं देता ?
75. सैनिकों और सुरक्षा बलों की सीमा पर लगातार हो रही हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?
76. सरकार ने बड़ी कंपनियों को बहुत सारी रियायतें दी हैं लेकिन देश के गरीबों के लिए उसने क्या किया ?
77. रेलवे का किराया और तरह–तरह के शुल्क बढ़ रहे हैं लेकिन रेलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही?
78. दलितों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया ?
79. सरकार स्किल्ड इंडिया की बात कर रही है, जो स्किल्ड हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल रही तो स्किल्ड इंडिया के तहत नया हुनर सीखने वालों के लिए रोज़गार कहाँ से आएगा ?
80. आपकी डबल इंजिन की सरकारों में कितने मंत्री स्वतंत्र निर्णय ले रहे है और कितने मंत्री आपकी तरह 18 –18 घंटे काम करते है ?
81. देश की 80 करोड़ जनता को आप की सरकार मुफ्त राशन बांट रही है तब नई संसद पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी ?
82. धर्म के नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी ?
83. क्या राम मंदिर बन जाने से यूवाओ को नौकरी, शिक्षा, बेटियो को सुरक्षा मिल जायेगी ?
84. क्या चुनाव में हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगना जरूरी है ? विकास के नाम पर या जनता के मुद्दो पर मांग नही सकते ?
85. अपनी छवि चमकाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करना जायज है ?

मोदी के कुशासन एवं जन विरोधी फैसले

1 देश के 14 प्रधानमंत्रियों के कुल मिलाकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। पिछले 9 साल में नरेन्द्र मोदी ने देश पर कर्जा 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज केवल मोदी ने लिया है। 2014 में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

2 डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 2014 में 3.54 पैसा था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 31 रू. तक पहुंचा दिया। 410 का सिलेंडर 1100 के पार केवल पेट्रोलियम उत्पाद से 30 लाख करोड़ से अधिक अतिरिक्त मुनाफाखोरी। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के रूप में देश की आम जनता की जेब से 30 लाख करोड़ की डकैती की।

3 रूपये का सर्वाधिक अमूल्यन मोदी राज में हुआ। एक डालर की कीमत 2014 में 59 रू. थी जो आज बढ़कर 83 रू. हो गया है। अर्थात 41 प्रतिशत अमूल्यन केवल मोदी राज में। मोदी जी कहते थे रूपये का मूल्य जितना गिरता है उतना केंद्र की सरकार भ्रश्ट होती है।

4 चंद पूंजीपति मित्रों के 18 लाख करोड़ से अधिक का लोन राईट ऑफ कर दिये लेकिन किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी–2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ का वादा करके भूल गये।

5 सेंट्रल एक्साइज जैसे केंद्रीय करो में कमी कर उसी अनुपात में सेस लगाया ताकि राज्यों को उसका हिस्सा न देना पड़े मोदी सरकार की नीतियां सहकारी संघवाद और राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ।

6 अडानी की कंपनी ने लगाये गये फर्जी सेल कंपनियों के 20 हजार करोड़ किसके है?

7 किसके दबाव में कंपनी एलआईसी और एसबीआई का पैसा अडानी की डूबती कंपनी में लगाया।

8 तमाम केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश कम करके राज्यांश बढ़ाया अर्थात राज्यों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया।

9 छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादक राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई 30 जून 2022 से बंद कर दी गयी। लेकिन क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिये वसूला जाने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। उत्पादक राज्यों की उपेक्षा क्यों?

10 केंद्र की मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी फिर गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) फिर कोविड मिस मैनेजमेंट से पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया।

11 केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिये देश के अन्नदाता किसानों पर कृशि के 3 काले कानूनों को थोपने का प्रयास किया। देश के किसान 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर आंदोलन करते रहे, कभी उन्हें अरबन नक्सली, आतंकवादी और पाकिस्तानी जैसे शब्दों से संबोधित कर अपमान किया गया। जब देश के 750 किसान परिवारों ने अपने परिवार के 1 सदस्य को खोया तब जाकर केंद्र की मोदी सरकार नींद से जागी।

12 वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल कर आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से वंचित करने केंद्र की मोदी सरकार शड़यंत्र रच रही है।

13 केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भारत देश भूखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पिछड़ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता शिखर पर पहुंच चुका है।

14 यूपीए सरकार में देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आये। जबकि केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे चले गये।

15 दैनिक उपभोग की वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाकर आम जनता से बेरहमी से कर वसूली करके कुल कर संग्रहण तो 3 गुना बढ़ा लिये लेकिन उसका लाभ और सुविधायें न राज्यों को, न ही आम जनता को।

16 10 दिन के भीतर अडानी की कंपनियों में निवेशकों के 15 लाख करोड़ की अधिक की राशि कैसे लूट गये? किसके संरक्षण में अडानी की कंपनियों एसेट बढ़ाकर बताये गये।

17 अपने पूंजीपतियों मित्रों के लाभ के लिये पहली बार देश में कर्मशियल माईनिंग मोदी सरकार ने प्रारंभ किया। कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल जैसे सरकारी कंपनियों और नौरत्न कंपनियों में खनन का काम अडानी को किसके दबाव में दिया गया।

18 भूपेश सरकार ने 27 जुलाई 2022 को हसदेव अरण्य के पांच कोल ब्लाक आंवटन निरस्त करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार को भेजा है। विगत एक वर्श से मोदी सरकार खामोश क्यों है?

19 यूपीए के समय तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला को अति जैव विविधता महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुये नो गो एरिया घोशित कर खनन गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी थी। जिसे मोदी सरकार ने संकुचित कर माइनिंग शुरू कराया।

20 कोरोना माहमारी के समय अपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने श्रम विरोधी दर्जनों कानून सदन में बिना चर्चा के ही पारित कर दिये।

21 02 दिसंबर 2022 से 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर राजभवन भेजा गया है, 9 माह से आखिर किसके इशारे पर और किसके दबाव में रोका गया है?

22 ब।ळ की रिपोर्ट के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपये प्रति किमी की लागत से बनना था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी लागत बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये प्रति किमी कर दी।

23 भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 75 हजार किमी सड़क बन रही है। ये सड़क 15 करोड़ प्रति किमी की लागत से बननी थी,लेकिन मोदी सरकार ने लागत 15 से 25 करोड़ रुपये प्रति किमी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया और अधिकांश काम अडाणी की कंपनियों को दे दिया।

24 जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश की गई और कहा गया कि छह राज्यों की छह परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19.73 करोड रुपये का गलत तरीके से लाभ दिया गया। अयोध्या स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट का हिस्सा है। इसके लिए 27 सितंबर 2017 को 127 करोड़ 21 लाख का बजट मंजूर हुआ था। इसमें से 115 करोड़ रुपये अभी तक जारी किए जा चुके हैं।

25 छडक्ब द्वारा निर्मित नगरनार स्टील प्लांट जिससे बस्तर के लोगों की सीधी भावनायें जुड़ी हुई है उसे केंद्र सरकार अपने मित्र अडानी को सौप कर निजीकरण करने की साजिश कर रही है। इसके अलावौ म्ब्स्- की 80 प्रतिशत से अधिक खदानों को पूंजीपति मित्र अडानी को सौपने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

26 छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिये यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुये लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द कर रही है। भाजपा के नौ लोकसभा सांसद केंद्र की मोदी सरकार के सामने छत्तीसगढ़ की हकों की बात करने में पूरी तरह असमर्थ है।

15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में 34 घोटाले किये भाजपा इन घोटालो का जवाब दे :—

रमन और उनके मंत्री मंडलीय सहयोगियों के घोटालों की सूची

1. 36000 करोड़ का नान घोटाला?
2. पनामा पेपर घोटाला।
3. मोवा धान घोटाला।
4. कुनकुरी चावल घोटाला।
5. आंख फोड़वा कांड। नकली दवाओं से लोगो की आंखो की रोशनी चली गयी।
6. गर्भाश्य कांड। स्मार्ट कार्ड के लिये महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिये। स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर थे।
7. नसबंदी कांड। नसबंदी कांड में महिलाओं पर नकली दवाओं का प्रयोग किया।
8. डीकेएस घोटाला।
9. शिवरतन शर्मा के भतीजे द्वारा किया गया धान परिवहन घोटाला।
10. शासकीय भूमि का कब्जा।
11. पोरा बाई कांड।
12. तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नि की जगह कोई और महिला बैठी परीक्षा देने।
13. फर्नीचर घोटाला।
14. विज्ञान उपकरण खरीदी में घोटाला।
15. 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला।
16. 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा, दवाई एवं निर्माण में किया घोटाला।

17. बीज निगम में दवाईया, बिज एवं कृशि यंत्रो की खरीदी में किया गया घोटाला
18. स्टेट वेयर हाउस के गोदामो के निर्माण में घोटाला।
19. स्वास्थ्य विभाग में मल्टी विटामिन सिरप में घोटाला।
20. जमीन घोटाला।
21. झलकी घोटाला (बृजमोहन अग्रवाल)।
22. परिवहन चेक पोस्ट पर घोटाला।
23. मोबाईल खरीदी में घोटाला।
24. बारदाना घोटाला।
25. भदौरा जमीन घोटाला (अमर अग्रवाल)।
26. पुश्प स्टील घोटाला।
27. चौबे कालोनी जमीन घोटाला।
28. इंदीरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला।
29. स्काई वाक घोटाला।
30. एक्सप्रेस वे घोटाला।
31. बिलासपुर सकरी बायपास घोटाला।
32. तेंदुपत्ता खरीदी घोटाला (300 करोड़)।
33. चिटफंड घोटाला।
34. रतन जोत घोटाला।

रमन राज में छत्तीसगढ़ का शोषण हुआ

1. **धान का समर्थन मूल्य 2100 रू. करने, किसानो को दिया झांसा** :– भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किसानों से वायदा किया था कि धान का प्रति क्वि. 2200 रू. समर्थन मूल्य देगें। चुनाव होने के बाद अपने वायदे से रमन सिंह मुकर गये।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई तब भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार 1875585 ग्रामीण हितग्राही थे लेकिन उस दौरान रमन सरकार ने मात्र 2 लाख 18 हजार ग्रामीण मकान स्वीकृत क्यो किया मध्यप्रदेश के 16 लाख 57 हजार 585 गरीबो को पीएम ग्रामीण आवास योजना से वंचित क्यो रखा। भूपेश सरकार में 1176146 ग्रामीण हितग्रहियों का आवास का सपना पूरा हुआ।
3. जनवरी 2018 में रमन सरकार ने राज्य को पूर्ण ओडीएफ घोषित करके प्रदेश के 15 लाख घरों को उन्नत शौचालय के अधिकार से वंचित रखा और राज्य के खजाने से 4000 करोड रुप्ए खर्च कर दिया।
4. **किसान आत्महत्या करने को मजबूर** : – छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, लेकिन रमन सिंह सरकार ने किसानों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। पिछले सालों में राज्य में करीब 2500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार के जिम्मेदार मंत्री कहते है कि किसान शराबी है जिसके कारण वे आत्महत्या कर रहे है। पिछले 15 वर्षों में राज्य में 15,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर लिया।
5. **किसानों को 5 हार्सपावर तक मुफ्त बिजली देने की झूठी घोषणा** :– रमन सरकार ने किसानों को 5 हार्सपावर पंप को मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था, उससे मुकरते हुए सरकार ने उसे सीमित कर 6000 यूनिट कर दिया है तथा किसानों को मनमाना बिजली का बिल भेजा जा रहा है। किसानों के बिजली के दामों में 300 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी
6. **कृषि यंत्रों की सब्सिडी में लाखों का घोटाला** :– कृषि विभाग में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में विभागीय अधिकारियों एवं पंजीकृत डीलरों द्वारा मिलीभगत कर सब्सिडी राशि की जमकर बंदरबांट की जा रही है। शासन द्वारा कृषि उपकरणों पर अनुदान लघु सीमांत कृषकों के लिए 50 प्रतिशत एवं दीर्ध किसानों के लिए 40 प्रतिशत तय किया है, किन्तु कृषि अधिकारियों एवं उपकरण विक्रताओं की सांठगांठ से किसानों की अनुदान राशि को डकार लिया जा रहा था और प्रदेश के किसान ठगे जा रहे थे।
7. **किसान विरोधी पुर्नवास नीति** :– छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुर्नवास नीति 2007 में दिनांक 4 जनवरी 2017 को गुपचुप तरीके से अधिसूचना जारी कर बदलाव किया जा रहा है, जो कि किसान विरोधी निर्णय है। पुर्नवास नीति में बदलाव के बाद भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूविस्थापित परिवारों को न तो मुआवजा मिलेगा और न ही रोजगार।

8. **गौशाला बना कसाईखाना** :– हिन्दू धर्म एवं गौमाता की दुहाई देने वाले भाजपा के नेताओं के द्वारा रमन सरकार के संरक्षण में गौशाला को कसाई खाना में तब्दील कर दिया था। सरकार से सुनयोजित तरीके से मुफ्त में जमीन हासिल कर सरकारी अनुदान से गौशाला खोले गये है, तथा प्रदेश भर से गायों को गौशाला में लाया गया एवं जानबूझकर भूखा रख कर मारा गया। गायों को मरने के बाद उसे चमड़ी, मांस एवं हड्डी का व्यापार किया गया। विभागीय अधिकारियों एवं गौशाला संचालकों के आपसी मिलीभगत से कमीशनखोरी कर करोंड़ो रूपयों का घोटाला किया था।
9. **पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिवारजन हड़प रहे शासकीय भूमि** :– प्रदेश के प्रभावशाली मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने परिवारजनों के नाम पर सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि को हड़पकर, उसमें निजी फार्म हाऊस बनाया है। महासमुंद जिले के जलकी गांव में 300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। फार्म हाउस के लिए खरीदी गई। 15.32 हेक्टेयर (लगभग 40 एकड़) भूमि अब भी राजस्व रिकार्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है।
10. **करोड़ों का नान (नागरिक आपूर्ति निगम)घोटाला** :– राज्य सरकार के संरक्षण में नागरिक आपूर्ति निगम में 36 हजार करोड़ रूपए का आर्थिक भ्रष्टाचार व घोटाला किया गया है। करोड़ो रू. एसीबी ने जब्त किए है। एसीबी द्वारा जब्त डायरी में मुख्यमंत्री एवं सीएम मैडम सहित प्रमुख अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं के नाम है किन्तु कोई जांच नही की गई थी।
11. **गरीबों के राशन में डाका** :– गरीब परिवार को मिलने वाले 35 किलो चावल को 7 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया, जिसके कारण गरीबों को परिवार का पेट पालने में परेशानी हो रही है। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। गरीबों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाने के कारण राशन प्राप्त नहीं हो रहा था।
12. **एम.ओ.यू. का फरेब, धरातल पर शून्य** :– प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों एवं पावर प्लांट की स्थापना हेतु सैकड़ो एम.ओ.यू. किये हैं। एम.ओ.यू. के निष्पादन में करोड़ों रूपयों के लेन–देन के आरोप हैं। ये एम.ओ.यू. छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के विरूद्ध किये गये हैं। क्योंकि इसमें परियोजनाओं के विस्थापितों के लिए पुनर्वास की समुचित कार्य योजना ही नहीं है। सरकार ने 67996 करोड़ के कुल 137 एम.ओ.यू. ही किये थे इसमें भी 80 प्रतिशत निवेशक स्थानीय है। आज तक इस एम.ओ.यू. का 10 प्रतिशत भी धरातल पर नहीं उतर पाया था।
13. **सर्वाधिक गरीबों वाला राज्य बना छत्तीसगढ़** :– राज्य के निर्माण के समय प्रदेश में 37 प्रतिशत गरीब रह रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 47.9 प्रतिशत गरीब रहते है। भिलाई में आकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंच से कह गए कि राज्य में एक करोड़ 30 लाख गरीब है जिनके जनधन खाते खोले गए है। यानी प्रधानमंत्री बता गए कि राज्य दरअसल 50 प्रतिशत गरीब है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में एक ओर गरीब और गरीब हो रहे है दूसरी ओर अमीर और अमीर हो रहे थे।
14. **आदिवासी परिवार को गाय एवं नौकरी देने के वादा से मुकरी सरकार** :– आदिवासी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने हर आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय, हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया गया, लेकिन ये भी जुमला निकलाथा।
15. **शराब कमीशन घोटाला** : – रमन सरकार स्वयं शराब का व्यापारी बन गई थी। शराब ठेकेदारों को मिलने वाले कमीशन को सरकार में बैठे लोग वसूल रहे थे। इस बात का आरोप मंत्रीमंडल में सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पांडे ने लगाया कि 1500 करोड़ का मिलने वाला कमीशन ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के बाद किसके जेब में जायेगा? इससे यह स्पष्ट है कि रमन सरकार शराब निर्माताओं से उनके ब्रांड का शराब बेचने के एवज में मिलने वाले कमीशन को वसूल रही थी।
16. **झलियामारी दुष्कर्म कांड प्रदेश के माथे पर कलंक** :– भाजपा राज में झलियामारी सरकारी आश्रम में 7 ये 13 साल की मासूम बच्चियों के लगातार महिनों दुष्कर्म होता रहा। लोगों ने बड़े भरोसे के साथ अपनी अबोध बच्च्यिों को सरकारी आश्रमों में भेजा था भाजपा सरकार ने इन अभिभावकों के भरोसे को तोड़ा झलियामारी के बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया। आमाबेड़ा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सरकारी कन्या आश्रमों में इस प्रकार की घृणित घटनाओं का दोहराव होते रहा। सरकार बेशर्मीपूर्वक मौन बैठी रहीथी।
17. **अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार** :– छ.ग. में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही है, पुलिस अभिरक्षा में मौंत हो रही है, किन्तु सरकार के कानों में जूं तक नही रेंग रही है। अनुसूचित जाति के खिलाफ प्रताड़ना के मामले में छ.ग. पूरे देश में दूसरे नंबर पर थी।
18. **आदिवासियों का शोषण, संवैधानिक अधिकारों का हनन** :– सरकार आदिवासियों की भलाई के बजाय बल्कि फर्जी एनकाऊंटर कर रही है। नक्सली के नाम से सैंकडों आदिवासी मारे गये हैं या जेल में ठूस दिये गये हैं। बस्तर में 700 गांवों का खाली होना इस बात का सबूत था।
19. **वनाधिकार कानून का पालन नही** :– आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी पात्र

लोगों को वनाधिकार का व्यक्तिगत पट्टा प्रदान करने में प्रदेश सरकार असफल रही है, सामुदायिक वनाधिकार प्रदेश में एक भी नहीं दिया गया था।

20. **आदिवासियों की जमीन हथियाने की साजिश** :– आदिवासियों के स्वामित्व की जमीन की अवैध तरीके से खरीदी बिक्री लगातार हो रही है, इसको रोक पाने में सरकार नाकाम रही है। उल्टे रमन सरकार ने विधानसभा में भू–राजस्व संहिता में संशोधन कर आदिवासियों की जमीन को हड़पने की साजिश की जिसे कांग्रेस ने विरोध कर नाकाम कर दियाथा।
21. **अडानी के हवाले खनिज संपदा** : – दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला खदान में अब तक एनएमडीसी का आधिपत्य रहा है। लेकिन अब सरकार डिपाजिट 13 में माइन डेवलपर कम आपरेटर की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रदेश के दूसरे कोयला खदानों को एक अडानी की कंपनी के हवाले करने के बाद अब लोहे के खदानों को भी अडानी की कंपनी को सौंपने का षड़यंत्र चल रहा है, यह भी बस्तरवासियों को धोखा देने वाला कदम था।
22. **भू अधिग्रहण कानून का उल्लंघन** :– उद्योग लगाने के नाम पर किसानों की जमीनों को सरकार अधिग्रहित कर उद्योगपतियों को दे रही है, भूमि अधिग्रहण कानून का पालन ना करते हुए उक्त भूमि पर पांच साल में उद्योग नहीं लगने पर किसानों को अधिग्रहित भूमि वापस नहीं किया जा रहा था।
23. **खनिज निधि का दुरूपयोग** :– आदिवासियों के हित में ही खनिज क्षेत्र कल्याण योजना बनाई गई थी। जिला खनिज न्यास का गठन कर,राशि को खर्च किया जाना था। ग्रामसभा के प्रस्ताव पर खर्च किया जाना चाहिए किन्तु इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इस राशि का खर्च प्रभावित क्षेत्रों की बजाए अन्य क्षेत्रों में खर्च कर दुरूपयोग किया जा रहा था।
24. **बदहाल शिक्षा व्यवस्था** : – रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बदहाल कर दिया है कि लोगों को लगने लगा है सरकार छत्तीसगढ़ के बच्चों को मजदूर बनाना चाहती है। पांचवी आठवीं के बच्चे लिखना पढ़ना नही जानते।बहुत से बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ रहे है। शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु वर्ष 2010–2011 से 2015–2016 तक राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा 8589 करोड़ आबंटित किया गया एवं राज्यांश 4790 करोड़ था कुल 13379 करोड़ में से मात्र 7592 करोड़ ही सरकार खर्च कर पाई। परिणाम स्वरूप शासकीय विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता निम्न स्तर की रहीथी।
25. **शिक्षक एवं सुविधा विहिन स्कूल** :– राज्य में शिक्षकों के 52,000, व्याख्याताओं के 12000 पद खाली हैं, तीन हजार स्कूलों में सिर्फ एक एक शिक्षक हैं, ऐसे अनगिनत स्कूल हैं जहां बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं था।
26. **3000 हजार शासकीय स्कूल बंद** :– रमन सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने स्कूल खोलने के बजाय प्रदेश में 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। सरकार की प्राथमिकता स्कूल खोलने के स्थान पर सरकारी शराब दुकानें खोलने में था।
27. **शिक्षा के अधिकार का गरीबों को लाभ नही** :– गरीबों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाकर शिक्षा का अधिकार दिला पाने में सरकार अक्षम रही है। प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला नही मिल रहा है। पालक अपने बच्चों को प्रवेश कराने भटकते रहते हैं। शिक्षा का अधिकार प्रदेश में मजाक बन गया था।
28. **महाविद्यालयों में सुविधाओं का अभाव** :– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापकों की कमी से जूझ रहे है। प्रदेश में संचालित 216 महाविद्यालयों में प्राचार्य के 106 पद रिक्त है, प्राध्यापक के 487 पद, सहायक प्राध्यापक के 1526 पद रिक्त है। क्रीड़ा अधिकारी के स्वीकृत 62 पद, ग्रंथपाल के 54 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रयोगशाला तकनीशियन तथा अन्य गैर शैक्षणिक पदों को भी सरकार नहीं भर पाई थी।
29. **लेपटाप देने का वादा पूरा नही** : – राज्य सरकार ने अपने घोषणा में महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों को लैपटाप व टेबलेट देने का वादा किया था, युवाओं को कालेज में प्रवेश लेते ही लेपटाप/टैबलेट वितरण की योजना झूठी साबित।
30. **स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल** : – देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे ने एक सर्वेक्षण के बाद बताया कि देश के 21 राज्यों में स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान 20 वां थ। छ.ग. में स्वास्थ्य की स्थिति भयावह हो गई थी, विभिन्न बीमारियों से लगातार मौतें हो रही है। भिलाई, दुर्ग एवं रायपुर में डेंगू से मौतों को सरकार रोकने में नाकाम रही थी।
31. **स्मार्ट कार्ड का घोटाला** :– स्मार्ट कार्ड के माध्यम से गरीबों को निजी अस्पतालों में ईलाज के नाम से किडनी निकाल लिया गया, गलत ईलाज के नाम से स्मार्ट कार्ड से पैसे हड़पे जा रहे है। घोटालेबाजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जा रही थी।
32. **जहरीली दवा से मौत (नसबंदी कांड़)** :– शासकीय लक्ष्य को पूरा करने सुविधाविहिन स्थान पर आपरेशन करने, जहरीली दवा की सप्लाई, ईलाज में लापरवाही के कारण बिलासपुर जिले के पेंडारी में नसबंदी शिविर में 19 से भी ज्यादा महिलाओं की मौतें हुई। जांच में पाया गया था कि सरकार के द्वारा जो दवाईयां उपलब्ध कराई गई है उसमें चूहेमार दवा मिली थी जिसके कारण मौत हुई थी।

33. **आंखफोडवा कांड** : — प्रदेश के बालोद एवं महासमुंद सहित कई जिलों में शासकीय नेत्र शिविर में गरीबों के आंख फोड़ने का कांड स्वास्थ्य विभाग के व्याप्त भ्रष्टाचार का साक्षात प्रमाण है। घटिया दवाई एवं सुविधाविहन स्थानों में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का उल्लंघन कर नेत्र शिविर का आयोजन किए गये थे।

34. **गर्भाशय कांड** :— महिलाओं को किया शर्मसार :— प्रदेश में महिलाओं को कैंसर का भय दिखाकर गर्भाशय निकालने का शर्मनाक कांड उजागर हुआ था। सरकार के संरक्षण में राज्य के विभिन्न नर्सिंग होम में सात हजार से ज्यादा आपरेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किए गए। इसके लिए शासन के माध्यम से इंश्योरेंश कंपनी ने 7 करोड़ 75 लाख का भुगतान किया गया,जिसमें से 70 फीसदी केवल गर्भाशय की सर्जरी के लिए दिया गया। पैसा कमाने के चक्कर में डाक्टरों ने कम उम्र की 28 से 30 साल की महिलाओं का भी आपरेशन कर डालाथा।

35. **अस्पतालों की दुर्दशा** : — प्रदेश के शासकीय अस्पताल भी राज्य शासन की उदासीनता का शिकार थ। अस्पताल नाम मात्र के लिए संचालित हो रहे हैं, वहां विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक अथवा अन्य तकनीकी अमला नहीं था। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सक के 1114 पद रिक्त था। चिकित्सक के 410 पद रिक्त था एवं नर्सिंग स्टाफ के 1512 पद रिक्त था। सरकार आदिवासी बाहुल्य जिलों में चिकित्सकीय अमला उपलब्ध करा पाने में पूर्णतरू अक्षम रही थी।

36. **प्रदेश में कुपोषण की स्थिति अत्यंत गंभीर** :— प्रदेश में कुपोषण की अत्यंत गंभीर स्थिति है। प्रदेश के 27 जिलों में कुपोषित बच्चों की संख्या चार लाख पचास हजार से भी ज्यादा था। प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे राजनांदगांव जिले में 33481 बच्चे है। राज्य में महिलाएं भी कुपोषण की शिकार है और 15 साल के शासन के बाद भी महिलाओं में कुपोषण की दर 37 प्रतिशत से ज्यादा था।

37. **बेटियों को बचाने में विफल** : — राज्य में लगभग 27,000 महिलाएं लापता थी और सरकार किसी को तलाश नहीं कर पाई थी, रमन सरकार के माथे पर मीना खल्खो और मड़कम हिड़मे जैसे हत्या के जघन्य आरोप लगे थे, मानवाधिकार आयोग ने बस्तर में अपनी जांच के बाद कहा था कि वहां सुरक्षाबलों ने कम से कम 16 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। कांकेर जिले के झलियामारी और बालोद जिले के आमागुड़ा में सरकारी कन्या आश्रमों में बच्चियों के साथ सामूहिक अनाचार होता रहा और सरकार देखती रहीथी।

38. **कमीशनखोरी मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति** : — छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार था। इस सरकार के उपर घोटालों की लंबी फेहरिश्त था। रायगढ़ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा सार्वजनिक मंच से भाजपा नेताओं, मंत्रीगणों को कमीशन खोरी से बाज आने की बात कहीं थी। उन्होंने कहा था कि, ''कमीशन 1 साल बंद कर दो, 30 साल नहीं हिलेगी सरकार''। रमन सिंह जी का यह बयान कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति थी।

39. **अंधेरे में डूबे हैं कई गांव** :— प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को झूठी जानकारी देकर 100 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की जानकारी दिया था जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल 122 ग्राम एवं 6191 बसाहटें विद्युत विहिन थी।

40. **6 हजार करोड़ का चिटफंड घोटाला** :— 6 हजार करोड़ के घोटाले जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार के लोग एवं परिवार के संरक्षण में चिटफंड कंपनी के कार्यालय खोले गये। बकायदा जिले के कलेक्टरों के द्वारा प्लेसमेंट के तहत चिटफंड कंपनियों में छ.ग. के बेरोजगारों को नौकरी दिलाई गई। पुलिस कंपनियों के डायरेक्टरों को गिरफ्तार ना कर छ.ग. के गरीब बेरोजगारों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर जेल भेजा गयाथा।

41. **झीरम घाटी की घटना की सीबीआई जांच से सरकार मुकरी** :— बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में झीरम घाटी में नक्सलवादियों के द्वारा 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में हमला कर कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार पटेल, श्री महेन्द्र कर्मा एवं श्री विद्याचरण शुक्ल सहित 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सरकार के द्वारा इस घटना की सीबीआई जांच कराने की घोषणा विधानसभा में की गई थी। वर्तमान में भाजपा एन.आई.ए. के माध्यम से जांच को रोक रही है। एन.आई.ए. झीरम की फाईल राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी को नहीं दे रही है।

42. **नक्सली समस्या का विस्तार** :— भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में गलत नीतियों के कारण छ.ग. के 14 जिले नक्सल प्रभावित हो गये थे। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला कवर्धा भी शामिल हो गया था। 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले डा. रमन सिंह कैसे विकास के रास्ते पर प्रदेश को ले जा रहे थे, यह उनके कवर्धा के नक्सल जिला में शामिल होने से पता चल जाता था।

43. **पनामा पेपर अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार** :— अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भ्रष्टाचार का उदाहरण देश के सामने आया है, जिसने छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का काम किया। जिस भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, वही यहां इस्तीफा देना तो दूर इस प्रकरण में जांच तक नही की जा रही है। पनामा पेपर के दस्तावेजों में इस कंपनी के डायरेंटर का नाम अभिषाक सिंह है एवं इस व्यक्ति का दस्तावेजों में लिखा पता श्शरमन मेडिकल स्टोर,न्यू बस स्टैण्ड वार्ड नं.—20,

विध्यवासिनी वार्ड, कवर्धा, छत्तीसगढ़ इंडियाश्श है, जो कि रमन सिंह के कवर्धा स्थित आवास का था।

44. **अगुस्ता हेलिकाप्टर खरीदी घोटाला** :– छत्तीसगढ़ की सरकार के विमानन विभाग द्वारा समस्त नियम–प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर शार्प ओशन इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड नामक हांगकांग की कंपनी से हेलिकाप्टर को 26 करोड़ 58 लाख 22 हजार रूपये में खरीद कर शासकीय कोष को करोड़ों रूपयों की क्षति पहुंचाई गई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा हेलिकाप्टर की खरीदी में ग्लोबल टेण्डर नहीं बुलाया गया, यही नहीं सिर्फ अगुस्ता से ही खरीदी करने के लिए खरीदी नियमों में भाजपा सरकार के मंत्रिमण्डल ने संशोधन कर दियाथा।

45. **फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी व्यक्तियों को सरकार का संरक्षण** :– छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर सैकड़ों लोग न केवल शासकीय नौकरी कर रहे थे, अपितु अन्य शासकीय योजनाओं का भी लाभ उठा रहे थे। सरकार की उदासीनता का फायदा उठाकर अनेक लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर चुनावों में निर्वाचित होकर राजनीति में भी सक्रिय थे।

46. **पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती** :– प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पंचायती राज के अधिकारों में लगातार कटौती करने से पंचायतें अब नाममात्र की संस्था रह गई थी, त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नही रह गया था। अधिकारी ना तो बैठकों में जाते थे, और ना ही किसी भी प्रकार की जानकारी देते थे। जनपद एवं जिला पंचायतों में प्रस्ताव पारित किये बिना अधिकारी आदेश पारित करते थे।

47. **उज्वला योजना गरीबों का चूल्हा हुआ बंद** :– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता रिफिलिंग नही करा पा रहे हैं।

48. **बारदाना खरीदी में घोटाला** :– प्रदेश में प्रतिवर्ष धान खरीदी हेतु बारदानों की जरूरत के अनुसार 1 हजार करोड़ रूपयों से अधिक के बारदाने खरीदे गये हैं,जो कि अमानक स्तर के हैं। विभाग द्वारा बारदाना खरीदी में जमकर घोटाला किया गया था।

49. **कोल–कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट 3000 हजार करोड़ की हानि** :– छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में कोल ब्लाक हासिल करने वाली कंपनियों से नियमानुसार नीलामी की राशि एवं रायल्टी के आधार पर स्टाम्प शुल्क लिया जाना था। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क के नियमों में आनन–फानन में अध्यादेश लाकर संशोधन कर दिया जिससे प्रदेश को लगभग 3000 करोड़ रूपयों की शुध्द हानि हुई थी।

50. **तेन्दूपत्ता बोनस घोटाला** :– सरकार आदिवासियों की गाढ़ी कमाई को अपने प्रचार में बर्बाद कर दी है। संग्रहण का खर्च काट कर तेन्दूपत्ता आय का वितरण करना कानूनी बाध्यता है। तेंदूपत्ता सीजन 2016 एवं 2017 की अवैध ढंग से रोकी गई थी।

51. **वनोपज का दाम कम, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था तार–तार** : – वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय यहां के आदिवासियों के जीवन का प्रमुख आधार है। 40 प्रतिशत जंगल और 32 फीसदी आदिवासी आबादी वाले राज्य में बड़ी संख्या में आदिवासी इन्हीं लघु वनोपजों के भरोसे रहते हैं। केन्द्र सरकार ने लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में भारी कटौती कर दी है, रंगीनी लाख के समर्थन मूल्य घटाकर 100 रू., कुसुमी लाख का 150 रू., इमली 18 रू., करंज बीज 18 रू., महुआ 20 रू., चिरौजी 60 रू. एवं हर्रा का दर घटाकर 8 रू. प्रतिकिलो कर दिया गया है। जो कि प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ था।

52. **रतनजोत घोटाला** :– प्रदेश सरकार ने नारा दिया था डीजल नही अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा अब बाड़ी से। पूरे प्रदेश में लोगों को सब्जबाग दिखा कर रतनजोत के पौधों का रोपण किया गया और लगभग 200 करोड़ रूपयों की राशि खर्च की गई। एक लीटर बायो डीजल भी नही बन पाया था।

53. **इंदिरा प्रियदर्शनीय बैंक घोटाला** :– इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक के घोटाले में 25 हजार 716 खाता धारकों के 54 करोड़ 38 लाख रूपए का गबन किया गया। मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं राजधानी के दो मंत्री को एक एक करोड़ देने की बात बताई थी,लेकिन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया गया और मामले को दबा दिया गया था।

54. **करोड़ों का टोकन घोटाला** :– प्रदेश के परिवहन विभाग अंतर्गत आरटीओ में टोकन के नाम पर करोड़ों रूपयों का खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा था। टोकन के बहाने वाहनों को ओवरलोडिंग की खुली छूट दी जा रही है। भाड़े के कर्मचारियों से अवैध वसूली कराया जा रहा था।

भाजपा आदिवासी विरोधी

- वन अधिकार पट्टों के लिये प्राप्त 4 लाख आवेदनों को बिना किसी परीक्षण के निरस्त कर दिया।
  (कांग्रेस सरकार ने 455586 वन अधिकार बांटे।)

- भाजपा सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार नहीं दिए गये।
  (कांग्रेस सरकार ने 50 लाख से अधिक सामुदायिक वन संसाधन)
- सैकड़ो निर्दोश आदिवासी को जेल लंबी अवधि तक कैद रखा।
  (विगत चार वर्शो में 1314 निर्दोश आदिवासी को कांग्रेस सरकार ने रिहा किया)
- भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया।
  (कांग्रेस की सरकार में बस्तर की लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांव में निजी इस्पात संयंत्र के लिये अधिग्रहित की गई 1707 किसानों की 4200 एकड़ से अधिक भूमि उन्हें वापस की)
- भाजपा शासनकाल में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी की जाती थी। लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया गया। संग्राहको को बिचौलियों को वनोपज औने–पौने दामों पर बेचना पड़ता था।
  (कांग्रेस राज में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 की।)
- पेसा कानून को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
  (कांग्रेस पेसा कानून के नियम बनाया)
- आदिवासियों को रोजगार, स्व रोजगार और उनकी आय में वृद्धि को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया।
- सुपोशण अभियान को लेकर प्रभावशील कार्य नहीं किया गया। वनांचल सुदूर क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगो तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया।
  फर्जी चिटफंड कंपनियों को आश्रय दिया गया। इन कंपनियों ने आम जनता से उनके खून पसीने की कमाई के करोड़ो रूप्ए ठगे।

भाजपा किसान विरोधी

1. भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में किसानों से एक–एक दाना धान खरीदने, 2100 रू प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने तथा 300 रू प्रति क्विंटल बोनस भी देने का वादा किया था। वह वादा छलावा मात्र सिद्ध हुआ।
   वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम यह निर्णय किया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं दी जायेगी। केंद्र सरकार के दबाव का ही परिणाम था कि किसानों से एक–एक दाना धान क्रय करने का वादा करने वाली रमन सरकार ने 2014 में ही यह घोषणा की कि किसानों से प्रति एकड़ मात्र 10 क्विंटल धान मात्र का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाये। कांग्रेस के उग्र विरोध एवं किसानों के आंदोलित होने से दबाव में आकर प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान खरीदी की सीमा बढ़ाकर 15 क्विंटल की गयी।
2. मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में घोषणा की थी कि आगामी 6 वर्षों में अर्थात वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जायेगी। किसानों की आय में वृद्धि होने के बदले आय कम हो गयी। इस घोषणा पर भी भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध ली है।
3. स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा अनुसार धान के एम.एस.पी. के निर्धारण करने के वादे से पलटना।
4. मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में 3 कृषि कानूनों को लाया गया। जिसका उद्देश्य एम.एस.पी. एवं पी.डी.एस. की व्यवस्था को समाप्त कर खेती का कार्पोरेटीकरण करना था। पूरे देश के किसानों ने मोदी सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया था। भाजपा के केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता पूरे देश में घूम–घूम कर यह समझाने का प्रयास करते रहे कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लागू किये जा रहे है तथा किसान नासमझी के कारण इनका विरोध कर रहे है। तीनों काले कानूनों का विरोध करते–करते 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद भी हठधर्मिता के कारण भाजपा नेताओं का दिल नहीं पसीजा। कुछ राज्यों के चुनाव निकट आने पर राजनीतिक हानि से बचने के लिये तीनों कानूनों को मजबूरी में वापस लेना पड़ा। लेकिन इससे भाजपा के किसान हितैषी बनने के ढोंग का पर्दाफाश हो गया ।

भाजपा का चरित्र आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग गरीब विरोधी

कांग्रेस सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देने विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवा कर राजभवन भेजा है। भाजपा ने शड़यंत्रपूर्वक उस विधेयक को राजभवन में रोके रखा है। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 76 प्रतिशत का आरक्षण सभी वर्गो की आबादी के अनुसार निर्णय लिया है। यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है।

लोकतंत्र था
मार दिया
CGPCC
COMMUNICATION DEPARTMENT
ED
CBI
IT
ED
लोकतंत्र
CONSTITUTION of INDIA
संविधान
छत्तीसगढ़